पीएम मोदी ने लॉन्च की क्वॉड फेलोशिप, 100 बेस्ट छात्रों को मिलेगा लाभ

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 161 दिनांक:25-05-2022 बुधवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

परस्पर सहयोग के अटूट विश्वास पर टिका है भारत और अमेरिका का रिश्ता : मोदी

ज्ञानवापी मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए जिला अदालत ने 26 मई की तिथि तय की

वाराणसी, (ईएमएस)। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में लगातार नए-नए तथ्यों के खुलासे के बाद मुकदमे की पोषणीयता से संबंधित मामले पर सुनवाई के लिए वाराणसी जिला अदालत ने 26 मई की तारीख नियत की है। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इस पर अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी।

सिंह ने बताया कि इसके साथ ही अदालत ने कमीशन की कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को एक सप्ताह का समय दिया है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने बताया कि उन्होंने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर यह कहा है कि यह मुकदमा सुनने लायक नहीं है क्योंकि ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई करना उपासना स्थल अधिनियम-1991 का उल्लंघन है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने पिछली 20 मई को ज्ञानवापी मामले को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

न्यायालय का कहना था कि चूंकि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है इसीलिए कोई तजुर्बेकार न्यायिक अधिकारी इस मामले को सुने। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएसएन नरसिम्हा और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा था कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में जरूर है लेकिन पहले इसे वाराणसी की जिला अदालत में सुना जाए। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि जिला जज आठ हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करें।

दिल्ली निवासी राखी सिंह तथा अन्य की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पिछली 26 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने का निर्देश दिया था। सर्वे का यह काम पिछली 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी। हिंदू पक्ष ने सर्वे के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने नकारते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है।

कुतुब मीनार मामले में पूजा पर सुनवाई पूरी, 9 जून को आएगा अदालत का आदेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली स्थित कुतुबमीनार में हिंदू मंदिर होने के दावे ने भी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त का वो विवादित मुद्दा है जिसका शोर इन दिनों न केवल सियासत को गर्म कर रहा है बल्कि आम लोगों की जिंदगी और सोच में भी हलचल पैदा कर रहा है। कुतुब मीनार मामले पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील के बीच मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। 9 जून को कुतुब मीनार मसले पर कोर्ट का आदेश आएगा। इससे पहले भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अपनी दलीलों में कहा है कि कुतुब मीनार में धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती क्योंकि वो स्मारक है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन ने कहा कि उनके पास 27 मंदिर को तोड़ वहां कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनाए जाने के पुख्ता सबूत हैं। इसलिए वहां उनको पूजा की इजाजत दी जाए।

कुतुब मीनार विवाद पर याचिकाकर्ता से कोर्ट से सवाल करते हुए पूछा, बिना पूजा 800 साल निकाल दिए तो फिर आज इसकी मांग क्यों हो रही है? कोर्ट ने ये भी पूछा कि, पूजा का अधिकार हमें कैसे मिला है? क्या ये मौलिक या संवैधानिक अधिकार है? याचिकाकर्ताओं ने साकेत कोर्ट को बताया कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई थी। हरिशंकर जैन ने कहा कि भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और मंदिर हमेशा मंदिर रहता है। इसके अलावा ये भी कहा कि पूजा के अधिकार से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवता लुप्त नहीं होते हैं।

एएसआई के वकील ने ये भी कहा कि 1914 में परिसर को नियंत्रण में लिया था और जब परिसर हमारे नियंत्रण में आया तब पूजा नहीं होती थी। एएसआई की तरफ से कहा गया है कि निचील अदालत का फैसला बिल्कुल ठीक था इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि, पूजा की मांग वाली याचिका खारिज की जाए।

गुजरात की टीम ने कटाया फाइनल का टिकट, राजस्थान के पास एक और मौका

नई दिल्ली, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रायल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में मैच खेला गयाइस मैच में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांडया ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जोस बटलर की 89 रन की धमाकेदार पारी के दम राजस्थान ने 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया और गुजरात को जीत के लिए 189 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में गुजरात की टीम ने राजस्थान को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। गुजरात की जीत में डेविड मिलर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का बड़ा योगदान रहा और उन्हें प्लेयर आफ द मैच भी चुना गया।

डेविड मिलर का हैट्रिक छक्का, गुजरात फाइनल में पहुंची

डेविड मिलर ने हैट्रिक छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। गुजरात टाइटंस पहली बार आइपीएल में शामिल हुई है और बड़े शान के साथ फाइनल में भी पहुंची। राजस्थान के खिलाफ इस टीम ने 19.3 ओवर में 3 विकेट पर 191 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज की। राजस्थान की टीम को बेशक इस मैच में हार मिली, लेकिन संजू सैमसन के पास अभी एक और मौका फाइनल में पहुंचने का है। एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी और लखनऊ में से जिसे जीत मिलेगी उस टीम को अब क्वालीफायर दो में राजस्थान के खिलाफ खेलना होगा। अगर उस मैच में राजस्थान को जीत मिल जाती है तो वो फाइनल में पहुंच जाएगी।

गुजरात की पारी, डेविड मिलर का अर्धशतक

गुजरात की टीम को पहला झटका दूसरी पारी के पहले ही ओवर में लग गया जब ट्रेंट बोल्ट ने साहा को सिल्वर डक पर आउट कर दिया। शुभमन गिल ने 21 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली और रन आउट हो गए। मैथ्यू वेड ने 35 रन की पारी खेली और मैककाय की गेंद पर जोस बटलर को अपना कैच थमा बैठे। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 38 गेंदों पर 5 छक्के व 3 चौकों की मदद से नाबाद 68 रन की पारी खेली जबकि कप्तान हार्दिक पांडया ने 27 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से नाबाद 40 रन बनाए। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 100 रन से ज्यादा की साझेदारी हुई।

राजस्थान की पारी, बटलर की फिफ्टी

टास हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान को दूसरे ओवर में यश दयाल ने झटका दिया। 3 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल विकेट के पीछे रिद्धिमान साहा को कैच दे बैठे। पहला विकेट गिरने के बाद कप्तान संजू सैमसन ने मैदान पर कदम रखा और टीम के स्कोर को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाया। पावरप्ले के 6 ओवर में टीम ने 1 विकेट पर 55 रन बनाए। बटलर ने इसमें 16 जबकि सैमसन ने 30 रन जोड़े।

26 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्के की मदद से कप्तान सैमसन 47 रन बनाकर साई किशोर की गेंद पर बाउंड्री पर जेसेफ को कैच दे बैठे। 30 गेंद पर 28 रन की पारी खेलने के बाद हार्दिक पांडया की गेंद पर देवदत्त पडिक्कल आउट होकर वापस लौटे। 89 रन का पारी खेलने के बाद आखिरी ओवर में दो रन लेने की कोशिश में बटलर रन आउट हुए।

संगठन में सुधारों के लिए कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों का कार्यबल समूह गठित किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। संगठन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए फैसलों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से मंगलवार को आठ सदस्यीय कार्य बल-2024 का गठन किया। साथ ही, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों का समूह भी गठित किया गया। पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कांग्रेस की दो अक्टूबर से प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय के लिए नौ सदस्यीय केंद्रीय योजना समूह का भी गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन महत्वपूर्ण समूहों का गठन किया।

कार्य बल-2024 में पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और चुनावी रणनीतिकार सुनील कानगोलू शामिल हैं। राजनीतिक मामलों के समूह में राहुल गांधी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कांग्रेस के जी 23 के दो अहम सदस्य गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को जगह मिली है। केंद्रीय योजना समूह में दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर और कुछ अन्य नेताओं को शामिल किया गया है।

सुरक्षित स्थान पर तबादले की मांग पर अडिग कश्मीरी पंडित, 10 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी

जम्मू (ईएमएस)। कश्मीर में असुरक्षा की भावना से भयभीत कश्मीरी पंडित अब विरोध पर उतर आए हैं। राहुल भट की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि हत्या के दिन से आज तक कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में श्रीनगर के राजबाग इलाके में कई इलाकों से आए कश्मीरी पंडितों ने राहुल भट की हत्या के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा के हालात ठीक होने तक सुरक्षित जगहों पर उनका ट्रांसफर किया जाये। राहुल भट के दसवें के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए लाल चौक पर प्रार्थना भी की। प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों ने जो बैनर लिये हुए थे उन पर लिखा था, ठहमारी एकमात्र मांग घाटी में रहने वाले सभी प्रवासी कर्मचारियों को भारत में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की है ताकि हमारे रक्तपात को रोका जा सके।''

ठहमें न्याय चाहिएठ के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने पंडित समुदाय के लोगों की लक्षित हत्याओं पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि आज के माहौल में वह कश्मीर घाटी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रभासाक्षी से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पिछले दस दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन जागे नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाता और हमें सुरक्षित स्थानों पर नहीं भेजता।

सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रोकी जगह-जगह फंसे तीर्थ यात्री

केदारनाथ (ईएमएस)। उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रही है। बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। फाटा और गौरीकुंड से हेली सेवा भी बाधित रही। रुद्रप्रयाग के सर्किल ऑफिसर प्रमोद घिल्डियाल ने कहा खराब मौसम की वजह से यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को रोका गया है। बारिश के कारण छह घंटे हेली सेवाएं रही बंद सोमवार को मौसम खराब होने के कारण केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं करीब 6 घंटे बंद रही। हालांकि 1 बजे बाद मौसम ठीक होने पर दोबारा हेली सेवाएं संचालित हुई। इस बीच एक कंपनी का हेलीकॉप्टर घंटों केदारनाथ में ही फंसा रहा जो 1 बजे मौसम खुलने के बाद वापस लौटा। इस बार मौसम केदारनाथ यात्रा में परेशानियां पैदा कर रहा है।

पंजाब कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने के कुछ देर बाद ही विजय सिंगला को पुलिस ने गिरफ्तार किया

चंडीगड़ (ईएमएस)। पंजाब के सीएम भगवंत मान की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत मंगलवार को पंजाब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के कुछ देर बाद विजय सिंगला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी है। सिंगला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सिंगला अपने विभाग की निविदाओं और खरीद में कथित रूप से एक प्रतिशत कमीशन मांग रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बने मुश्किल से दो महीने ही हुए हैं। सिंगला (52) मनसा विधानसभा सीट से विधायक हैं।

क्वाड सम्मेलन में रूस का नाम लिए बिना यूक्रेन पर पीएम मोदी ने अपना नजरिया रखा

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में रूस का नाम लिए बिना यूक्रेन पर अपना नजरिया रखा। पीएम मोदी ने दुनिया के सभी शीर्ष नेताओं के समक्ष शत्रुता समाप्त करने की बात कही। उन्होंने एक बार फिर कहा कि संवाद और कूटनीति के जरिए ही युद्ध समाप्त किया जा सकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रूस का जिक्र नहीं किया लेकिन यूक्रेन पर बात करते हुए दुनिया को बड़ा संदेश दिया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टोक्यो में दूसरे व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स समिट में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने शत्रुता को समाप्त करने, संवाद और कूटनीति को फिर से शुरू करने की आवश्यकता कही। पीएम मोदी ने क्वाड देशों के नेताओं के साथ चौथी बातचीत में भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। जिसमें यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई की आलोचना हुई।

पीएम मोदी ने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष के बीच कूटनीति पथ के लिए खड़ा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि इस युद्ध ने दोनों देशों को भारी नुकसान दिया है और यूरोप में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट खड़ा हो गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान सभी वैश्विक नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने इंडो-पैसिफिक में विकास और यूरोप में संघर्ष पर अपना दृष्टिकोष रखा।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, क्वाड लीडर्स समिट में नेताओं ने आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी इच्छा दोहराई। साथ ही आतंकवादी समूहों को किसी भी सैन्य, वित्तीय या सैन्य सहायता से इनकार करने के महत्व पर जोर दिया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए क्वाड के चल रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए नेताओं ने भारत में जैविक-ई सुविधा की बढ़ी हुई विनिर्माण क्षमता का स्वागत किया और डब्ल्यूएचओ द्वारा ईयूएल अनुमोदन के शीघ्र अनुदान का आह्वान किया ताकि टीकों की डिलीवरी शुरू हो सके।

एमईए के मुताबिक, ठनेताओं ने क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के तहत अप्रैल 2022 में थाईलैंड और कंबोडिया को भारत द्वारा मेड इन इंडिया टीकों की 525,000 खुराक के उपहार का स्वागत किया।ठ एमईए ने एक बयान में कहा, जीनोमिक निगरानी और नैदानिक परीक्षणों में सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाना और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा वास्तुकला को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ने कोरोना टीकों, दवाओं और चिकित्सा विज्ञान के निर्माण और बाल चिकित्सा वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता के लिए एक त्वरित विश्व व्यापार संगठन से छूट का आह्वान किया।

ओवैसी के पोस्ट पर विवाद, मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं?

नई दिल्ली (ईएमएस)। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। ओवैसी ने पोस्ट में कहा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। इसके साथ सवाल उठाया कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं? ओवैसी के पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि वहां हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। अम्मू ने कहा कि ओवैसी ने बयान से यह साफ कर दिया है, कि मुगलों ने सिर्फ लूटपाट ही नहीं की बल्कि बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ भी किया।

ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा-शाही ईदगाह, ताजमहल और कुतुबमीनार विवाद के बीच इतिहास को लेकर आजकल बहस छिड़ी हुई है। इस दौरान ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले को औरंगजेब से जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि बात निकली तब दूर तक जाएगी। ओवैसी ने विवादित पोस्ट किया है। ओवैसी ने लिखा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है।

ओवैसी ने लिखा कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है लेकिन ये बताओ की मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं। ओवैसी ने इससे पहले गुजरात के सूरत में रैली को सम्बोधित करते हुए कहा था बीजेपी पुष्यमित्र की ओर से तोड़े गए बौद्ध मंदिरों की बात क्यों नहीं करती।

पंजाब- सीएम मान का बड़ा फैसला, कमीशनखोरी के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री को किया बर्खास्त

चंडीगढ (ईएमएस)। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने नेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मात देते हुए बड़ा फैसला किया और अपनी कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के आरोप में बर्खास्त कर दिया। आपको याद होगा सीएम केजरीवाल के वो विज्ञापन जिसमें वो कहते नजर आते थे, कोई आपसे रिश्वत मांगे तो मना मत करना बल्कि उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब की नई नवेली भगवंत मान सरकार ने भी भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। लेकिन अब भगवंत मान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। सिंगला पर अधिकारियों से कमीशन मांगने का आरोप लगा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मान को स्वास्थ्य मंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख्ता सबूत मिले थे। इसके साथ ही पंजाब सीएम ने सिंगला के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि एक दशक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए विजय सिंगला लंबे वक्त से सिविस अस्पताल मानसा रोड पर एक डेंटल क्लीनिक चला रहे हैं। उनकी पत्नी अनीता सिंगला भी बीएएमएस हैं और बेटा चेतन सिंगला एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में डॉ. सिंगला ने मानसा से प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धी मूसेवाला को 60 हजार से अधिक मतों से पराजित किया था।

जब भारत चुप हो जाता है, तब 'बेजान' हो जाता है, यहां बोलने की अनुमति देने वाली संस्थाओं पर हमला हो रहा है : राहुल गांधी

कैंब्रिज, ब्रिटेन (ईएमएस)। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित 'कैंब्रिज विश्वविद्यालय' के 'कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज' में सोमवार शाम आयोजित 'इंडिया एट 75' कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार पर नाम लिए बगैर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि भारत को बोलने की इजाजत देने वाली संस्थाओं पर 'सुनियोजित हमला' हो रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत को बाधित किए जाने के कारण 'सरकार की नीतियों को गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोग या एजेंसियां' देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। राहुल ने छात्रों, विशेषकर भारतीय मूल के छात्रों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका और देश के लोगों को संगठित करने के प्रयासों जैसे व्यापक विषयों पर अपनी राय साझा की।

विश्वविद्यालय में भारतीय मूल की शिक्षाविद डॉ. श्रुति कपिला के साथ बातचीत में राहुल ने उन सभी बिंदुओं को दोहराया, जिनका जिक्र उन्होंने पिछले सप्ताह एक सम्मेलन के दौरान किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भारतीय राजनीति पर 'सरकारी नीतियों को कथित तौर पर गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोगों या एजेंसियों' के प्रभाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए भारत तब 'जीवंत' होता है, जब भारत बोलता है और जब भारत चुप हो जाता है, तब यह 'बेजान' हो जाता है। मैं देखता हूं कि भारत को बोलने की अनुमति देने वाली संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है- संसद, चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर एक संगठन द्वारा कब्जा किया जा रहा है।' राहुल ने कहा, 'बातचीत को बाधित किए जाने के कारण 'सरकारी नीतियों को गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोग या एजेंसियां' इन रिक्त स्थानों में प्रवेश कर रही हैं और देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं।'

कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी की लड़ाई धन के बड़े पैमाने पर केंद्रीकरण और मीडिया सहित देश के भीतर अन्य संस्थानों पर कब्जा करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'आप भारतीय मीडिया में कहीं भी 30 सेकंड से अधिक इस बात को नहीं देख पाएंगे। इसका कारण भारतीय मीडिया पर कब्जा है। भारतीय मीडिया को सरकार का समर्थन करने वाले कुछ बड़े उद्योगपति नियंत्रित कर रहे हैं। इसलिए, हम एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारत राष्ट्र पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं और यह आसान नहीं है।।।इसमें समय लगेगा। यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम कोशिशें जारी रख रहे हैं।'

यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस 'हिंदू राष्ट्रवाद' की विचारधारा से लड़ने की योजना कैसे बना रही है, राहुल ने कहा कि वह इस शब्द से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'इसमें 'हिंदू' जैसा कुछ नहीं है और वास्तव में इसमें कुछ भी राष्ट्रवादी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उनके लिए एक नया नाम सोचना होगा, लेकिन वे निश्चित रूप से 'हिंदू' नहीं हैं। आपको यह बताने के लिए मैंने हिंदू धर्म का विस्तार से अध्ययन किया है। लोगों की हत्या करना और उन्हें पीटना 'हिंदू' होना नहीं है।'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को राहुल पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से भारत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा था कि विदेशी धरती से भारत के बारे में लगातार की जा रही उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी देश को धोखा देने के समान है। राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी अगस्त में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद अक्टूबर-नवंबर से लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ने के तरीके के रूप में पदयात्राओं के साथ जमीनी स्तर पर लोगों से मिलने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की योजना पर काम कर रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी को गांधी परिवार से बाहर नेतृत्व की जरूरत है, उन्होंने कहा, 'यह कांग्रेस पार्टी को तय करना है। अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है, पार्टी को इस पर फैसला करना है।' भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के तहत कैंब्रिज विश्वविद्यालय के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस द्वारा आयोजित कार्यक्रम का समापन राहुल के साथ हुए इस संवाद के साथ हुआ।

श्री कृष्ण जन्मस्थान, शाही ईदगाह मामला-हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मथुरा न्यायालय में दाखिल

मथुरा (ईएमएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मथुरा की अदालत को श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले चार माह में निपटाने के दिए गए आदेश की कॉपी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। पक्षकार मनीष यादव का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में अब चार महीने में न्याय मिलने की उम्मीद है। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे सभी वादों को चार महीने में निपटाने के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए थे। श्री कृष्ण जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए मथुरा की सिविल कोर्ट में मनीष यादव ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में जल्द सुनवाई के लिए मनीष यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को चार महीने में निपटाने के आदेश दिए थे। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मथुरा की अदालत में दाखिल करने के बाद मनीष यादव ने बताया कि अब उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया समय शुरू हो गया है।

कार्टून कोना

केंद्र सरकार ने दी लापता कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील, तुरंत मिलेगी पेंशन

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र ने लापता कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित इलाकों के साथ-साथ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वालों के परिजनों के लिए एक बड़ी राहत है। एक आदेश के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, परिवार पेंशन का लाभ तुरंत परिवार को दिया जाएगा और यदि वह फिर से आता है तथा सेवा शुरू करता है, तो लापता होने की अवधि के बीच के समय में पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी गई रकम उसके वेतन से काटी जा सकती है।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इससे पहले, परिवार पेंशन का भुगतान तब तक नहीं किया जाता था जब तक कि लापता सरकारी कर्मचारी को कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था या उसके लापता होने के सात साल बीत नहीं जाते थे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक होती हैं।

कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने और उन्हें और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत आने वाला कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, तो लापता कर्मचारियों के परिवारों को वेतन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, आदि के बकाये का लाभ दिनांक 25 जून 2013 को जारी निर्देशों के मुताबिक दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है और ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, समान लाभ (जैसा कि सीसीएस (पेंशन) नियम में लागू है) का विस्तार एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के परिवार तक भी करने का निर्णय लिया गया है।

बयान में कहा गया कि वेतन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के बकाये का लाभ परिवार को उन सभी मामलों में दिया जाएगा जहां एनपीएस के तहत आने वाला एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, भले ही कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के अंतर्गत लाभ के लिए विकल्प का प्रयोग किया हो।

जन हितैषी

एंथनी का चीन प्रेम

आस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। यहां हुए आम चुनावों में लिबरल पार्टी की हार हुई है। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बानीस देश के अगले पीएम होंगे। वैसे तो यहां 6 दावेदार प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला मॉरिसन के गठबंधन और लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बानीस के बीच माना जा रहा था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को पिछले चुनावों में भी बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जापान में होने जा रहे क्वॉड देशों के शिखर सम्मेलन को देखते हुए स्कॉट मॉरिसन ने तत्काल अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया। मॉरिसन की हार के बाद अब विपक्षी नेता एंथनी अल्बानीस प्रधानमंत्री बनेंगे। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बानीस के बारे में कहा जाता है कि वह चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को संतुलित कर सकते हैं जो स्कॉट मॉरिशन के कार्यकाल में रसातल में चले गए थे। अल्बानीस के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनने पर पेन्नी वोंग विदेश मंत्री बन सकती हैं जो चीन-मलेशियाई मूल की हैं और फर्राटे से चीनी भाषा बोलती हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि चीन के साथ रिश्तों को संतुलित किया जाएगा जो मॉरिसन के कार्यकाल में बहुत खराब हो गए थे। चीनी मूल के ऑस्ट्रेलियाई वोटरों को रिझाने के लिए वोंग ने चीनी भाषा के प्रसार पर ज्यादा पैसा खर्च करने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा में उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए। वोंग ने कहा कि पूरे इलाके में बदलाव में अमेरिका हमारा अभिन्न सहयोगी जरूर है साथ ही अन्य भागीदारों और रिश्तों को मजबूत करना होगा। इसका मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में और ज्यादा काम करना है। यह किसी से छिपा नहीं है कि नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे एंथनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लंबे समय से प्रशंसक रहे हैं। यही नहीं लेबर पार्टी पर अरबपति हुआंग शिंआंगमो से 1 लाख डॉलर चंदा लेने के भी आरोप लगे हैं। वहीं एंथनी का भारत के साथ खास रिश्ता रहा है और वह भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जंगल में लगी सबसे बड़ी आग के दौरान हवाई द्वीप पर छुट्टियां मनाना, कोरोना वैक्सीन को सही समय पर हासिल करने में असमर्थ रहने और जरूरी मौकों पर एक्शन नहीं लेने की वजह से मॉरिसन को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के मतदाताओं ने जलवायु परिवर्तन, चीन और कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपना वोट दिया था। मॉरिसन ने जलवायु परिवर्तन को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना उन्हें लेना चाहिए था। यही नहीं ऑस्ट्रेलिया की नाक के नीचे चीन सोलोमन द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है और मॉरिसन को इसकी हवा तक नहीं लगी। मॉरिसन ने बहुत लंबे समय कोरोना लॉकडाउन लगाए रखा जिससे जनता में काफी गुस्सा देखा गया। नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे एंथनी अल्बानीस ने खुलकर कहा है कि चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते जटिल बने रहेंगे लेकिन चीन के साथ निपटने का एक परिपक्व तरीका भी है। उन्होंने कहा कि घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए भड़काऊ बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने संकेत दिया है कि चीन के साथ रिश्तों को संतुलित किया जाएगा जो मॉरिसन के कार्यकाल में बहुत खराब हो गए थे। यह किसी से छिपा नहीं है कि नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे एंथनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लंबे समय से प्रशंसक रहे हैं। यही नहीं लेबर पार्टी पर अरबपति हुआंग शिंआंगमो से 1 लाख डॉलर चंदा लेने के भी आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट में चीनी जासूसों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि लेबर पार्टी के सांसद जीत सकें। यही नहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एंथनी की जमकर तारीफ की है। वहीं चीन के नए राजदूत इसे बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं और अपनी बयानबाजी के टोन को धीमा किया है। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों को लेकर भी दुनिया की नजरें हैं। लेबर पार्टी की जीत के बाद क्या भारत को ऑस्ट्रेलिया से कोयला और रेअर अर्थ मिलने में दिक्कत होगी? यह बड़ा सवाल उठ रहा है।

मंदिर-मस्जिद साथ-साथ क्यों न रहें?

मंदिर-मस्जिद विवाद पर छपे मेरे लेखों पर बहुत-सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग तरह-तरह के सुझाव दे रहे हैं ताकि ईश्वर-अल्लाह के घरों को लेकर भक्तों का खून न बहे। पहला सुझाव तो यही है कि 1991 में संसद में जो कानून पारित किया था, उस पर पूरी निष्ठा से अमल किया जाए याने 15 अगस्त 1947 को जो धर्म-स्थान जिस रूप में था, उसे उसी रूप में रहने दिया जाए। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह कानून संसद में बनवाया था, वह भी इस बात को जोरदार ढंग से नहीं दोहरा रही है। उसे डर लग रहा है कि यदि वह ऐसा करेगी तो उसका हिंदू वोट बैंक, जितना भी बचा है, वह भी लुट जाएगा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कांग्रेस की कब्रगाह बन सकता है। तो अब क्या करें? इस समस्या के हल का दूसरा विकल्प यह है कि 1991 के इस कानून को भाजपा सरकार रद्द करवा दे। यह मुश्किल नहीं है। भाजपा का स्पष्ट बहुमत तो है ही, वोटों के लालच में छोटी-मोटी पार्टियां भी हां में हां मिला देंगी। तो क्या होगा? तब भाजपा सरकार के पास अगले दो-तीन साल तक एक ही प्रमुख काम रह जाएगा कि वह ऐसी हजारों मस्जिदों को तलाशे, जो मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई हैं। यह काम ज्यादा कठिन नहीं है। अरबी और फारसी के कई ग्रंथ और दस्तावेज पहले से उपलब्ध हैं, जो तुर्क, मुगल और पठान बादशाहों के उक्त ''पवित्र कर्म' का बखान करते हैं। वे धर्मस्थल स्वयं इसके साक्षात प्रमाण हैं। तो क्या इन मस्जिदों को तोड़ने का जिम्मा यह सरकार लेगी? ऐसे अभियान की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या सरकार बर्दाश्त कर सकेगी? इस समस्या का तीसरा विकल्प यह हो सकता है, जैसा कि कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बयान दिया है कि भारत के सारे मुसलमान उन सभी मस्जिदों का बहिष्कार कर दें और हिंदुओं को सौंप दें ताकि वे उन्हें फिर से मंदिर का रूप दे दें। यह सुझाव तो बहुत अच्छा है। भारत के मुसलमान ऐसा कर सकें तो वे दुनिया के बेहतरीन मुसलमान मान जाएंगे और वे इस्लाम की इज्जत में चार चांद लगा देंगे लेकिन क्या यह संभव है? शायद नहीं। तो फिर क्या किया जाए? एक विकल्प जो मुझे सबसे व्यावहारिक और सर्वसंतोषजनक लगता है, वह यह है कि यदि मुसलमान मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हैं और हिंदू लोग मंदिर को ईश्वर का घर मानते हैं तो अब दोनों घर एक-दूसरे के पास-पास क्यों नहीं हो सकते? क्या ईश्वर और अल्लाह अलग-अलग हैं? दोनों एक ही हैं। 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के ढह जाने के बाद जो 63 एकड़ जमीन उसके आस-पास नरसिंहराव सरकार ने अधिग्रहीत की थी, वह मेरा ही सुझाव था। उस स्थान पर अपूर्व एवं भव्य राम मंदिर तो बनना ही था, उसके साथ-साथ वहां पर दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का संयुक्त धर्म-स्थल भी बनना था। इसी काम को अब देश के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर जन-सहयोग से प्रेमपूर्वक संपन्न किया जा सकता है।

(लेखक/ईएमएस-डॉ. वेदप्रताप वैदिक)

दैनिक पंचांग

25 मई 2022 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	वृष में	मिथुन	06.42 बजे से
चंद्र	मीन में	कर्क	08.55 बजे से
मंगल	मीन में	सिंह	11.11 बजे से
बुध	वृष में	कन्या	13.23 बजे से
गुरु	मीन में	तुला	15.34 बजे से
शुक्र	मेष में	वृश्चिक	17.48 ब.से
शनि	कुंभ में	धनु	20.04 बजे से
राहु	मेष में	मकर	22.10 बजे से
केतु	तुला में	कुंभ	23.56 बजे से
राहुकाल 12.00 से 1.30 बजे तक		मीन	01.29 बजे से
		मेष	03.00 बजे से
		वृष	04.40 बजे से

बुधवार 2022 वर्ष का 145 वां दिन
दिशाशूल उत्तर **ऋतु** ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2079 **शक संवत्** 1944
मास ज्येष्ठ (दक्षिण भारत में वैशाख)
पक्ष कृष्ण **तिथि** दशमी 10.33 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** उत्तराभाद्रपदा 23.20 बजे को समाप्त। **योग** प्रीति 22.44 बजे को समाप्त। **करण** विष्टि 10.33 बजे तदनन्तर बव 22.40 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 24.2 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 20° 54'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1871259
जूलियन दिन 2459724.5
कलियुग संवत् 5123
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2548
हिजरी सन् 1443
महीना सव्वाल
तारीख 23
विशेष हनुमान जयंती(तेलुगु)।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
लाभ	05.54 से	07.22 बजे तक	उद्वेग	05.41 से	07.12 बजे तक
अमृत	07.22 से	08.51 बजे तक	शुभ	07.12 से	08.44 बजे तक
काल	08.15 से	10.19 बजे तक	अमृत	08.44 से	10.16 बजे तक
शुभ	10.19 से	11.47 बजे तक	चर	10.16 से	11.47 बजे तक
रोग	11.47 से	01.16 बजे तक	रोग	11.47 से	01.19 बजे तक
उद्वेग	01.16 से	02.44 बजे तक	काल	01.19 से	02.51 बजे तक
चर	02.44 से	04.12 बजे तक	लाभ	02.51 से	04.23 बजे तक
लाभ	04.12 से	05.41 बजे तक	उद्वेग	04.23 से	05.54 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

टूटते संबंध, बढ़ता अवसाद

मनुष्य जिस तीव्र गति से उन्नति कर रहा है, उसी गति से उसके संबंध पीछे छूटते जा रहे हैं. भौतिक सुख-सुविधाओं की बढ़ती इच्छाओं के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं. माता-पिता बड़ी लगन से अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं. उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. परिवार में लड़कियां हैं, तो वे विवाह के पश्चात ससुराल चली जाती हैं और लड़के नौकरी की खोज में बड़े शहरों में चले जाते हैं. इस प्रकार वृद्धावस्था में माता-पिता अकेले रह जाते हैं. इसी प्रकार शहरों में उनके बेटे भी अकेले हो जाते हैं.

संयुक्त परिवार टूटने के कारण एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं. एकल परिवारों के कारण संबंध टूट रहे हैं. संयुक्त परिवारों में बहुत से रिश्ते होते थे. दादा-दादी, ताया-ताई, चाचा-चाची, बुआ-फूफा, नाना-नानी, मामा-मामी, मौसी-मौसा तथा उनके बच्चे अर्थात बहुत से भाई-बहन. बच्चे बचपन से ही इन सभी संबंधों को जानते थे, परन्तु अब एकल परिवारों में माता-पिता और उनके दो या एक बच्चे ही हैं. संयुक्त परिवार टूटने के अनेक कारण हैं. रोजगार के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों में बढ़ते मतभेद, कटुता एवं स्वार्थ आदि के कारण भी एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति नितांत अकेला पड़ता जा रहा है. संयुक्त परिवार में समस्याएं सांझी होती थीं. व्यक्ति किसी कठिनाई या समस्या होने पर परिवार के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर लेता था. इस प्रकार उसे समस्या का समाधान घर में ही मिल जाता था.

संयुक्त परिवार के बहुत से लाभ हैं. परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा का दायित्व सबका होता है. किसी भी सदस्य की समस्या पूरे परिवार की होती है. यदि किसी को पैसे आदि की आवश्यकता है, तो पैसे बाहर किसी से मांगने नहीं पड़ते. परिवार के सदस्य ही मिलजुल कर सहयोग कर देते हैं. परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण घर और बाहर के कार्यों का विभाजन हो जाता है. प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य कर लेता है तथा अन्य कार्यों से मुक्त रहता है. ऐसे में उसे अपने लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार में रसोई एक होने के कारण खर्च भी कम हो जाता है. उदाहरण के लिए दो या तीन एकल परिवार यदि संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, तो उन्हें अधिक सामान की आवश्यकता होगी. थोक में अधिक सामान लेने पर वह सस्ता पड़ता है. इसी प्रकार तीन के बजाय एक ही फ्रिज से काम चल जाता है. ऐसी ही और भी चीजें हैं. परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर उसकी ठीक से देखभाल हो जाती है. परिवार के सदस्य साथ रहते हैं, तो उनमें भावनात्मक लगाव भी बना रहता है. इसके अतिरिक्त बच्चों का पालन-पोषण भी भली-भांति आसानी से हो जाता है. उनमें अच्छे संस्कार पैदा होते हैं. वे यह भी सीख जाते हैं कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए. इसमें बड़ों का सम्मान करना, अपनी आयु के लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करना तथा छोटों से स्नेह रखना आदि सम्मिलित हैं.

आज परिस्थितियां पृथक हैं. मनुष्य किसी भी कठिनाई या किसी संकट के समय स्वयं को अकेला ही पाता है. यदि परिवार में महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तब भी उसे घर का सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में अन्य महिलाएं होने के कारण उसे आराम करने का समय मिल जाता था. साथ ही उसकी भी उचित प्रकार से देखभाल भी हो जाती थी.

एकल परिवार में अकेले पड़ जाने के कारण व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है. अवसाद एक मानसिक रोग है. इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को निराश अनुभव करता है. वह स्वयं को अत्यधिक लाचार समझने लगता है. ऐसी स्थिति में प्रसन्नता एवं आशा उसे व्यर्थ लगती है. वे अपने आप में गूम रहने लगता है. वह किसी से बात करना पसंद नहीं करता. हर समय चिड़चिड़ा रहता है. यदि कोई उससे बात करने का प्रयास करता है, तो वे क्रोधित हो जाता है. कभी वह उसके साथ असभ्य अथवा उग्र व्यवहार भी करता है. मनोचिकित्सकों के अनुसार अवसाद के भौतिक कारण भी होते हैं, जिनमें आनुवांशिकता, कुपोषण, गंभीर रोग, नशा, कार्य का बोझ, अप्रिय स्थितियां आदि प्रमुख हैं. अवसाद की अधिकता होने पर व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है. अवसाद के कारण आत्महत्या करने के अप्रिय समाचार सुनने को मिलते रहते हैं. ऐसे विचलित करने वाले समाचार भी मिलते हैं कि अमुक व्यक्ति ने सपरिवार आत्महत्या कर ली या परिवार के सदस्यों की हत्या करने के पश्चात स्वयं भी आत्महत्या कर ली.

कोरोना काल में जहां संयुक्त परिवारों के लोग एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, वहीं एकल परिवारों के लोग अवसाद का शिकार होने लगे. 'द लैंसेट पब्लिक हेल्थ' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों में अवसाद एवं घबराहट की शिकायतें देखने को मिल रही है. सात दिन या उससे अधिक समय तक कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित रहे लोगों में अवसाद एवं घबराहट की दर उन लोगों की तुलना में अधिक थी, जो संक्रमित रोगी कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए अर्थात वे अपने परिजनों के मध्य ही रहे. रिपोर्ट के अनुसार सार्स-कोव-2 संक्रमण वाले ऐसे रोगी जो अस्पताल में भर्ती हुए उनमें 16 महीने तक अवसाद के लक्षण देखे गए, परन्तु जिन रोगियों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, उनमें अवसाद और घबराहट के लक्षण दो महीने के भीतर ही कम हो गए. सात दिनों या उससे अधिक समय तक बिस्तर पर रहने वाले लोगों में 16 महीने तक अवसाद और घबराहट की समस्या 50 से 60 प्रतिशत अधिक थी.

मनोचिकित्सकों के अनुसार अवसाद से निकलने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ समय व्यतीत करे. किसी भी समस्या या संकट के समय परिजनों से बात करे. स्वयं को अकेला न समझे. सकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से बात करे. परिजनों को भी चाहिए कि वे अवसादग्रस्त लोगों में सकारात्मक विचार पैदा करने का प्रयास करें, उन्हें अकेला न छोड़ें, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से अपराध की ओर अग्रसर हो सकते हैं. उन्हें उनकी किसी भी नाकामी के लिए तानें न दें, अपितु उनको प्रोत्साहित करें तथा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं.

वास्तव में आज तकनीकी ने समस्त संसार के लोगों को जितना समीप कर दिया है, उतना ही एक-दूसरे से दूर भी कर दिया है. मोबाइल के माध्यम से व्यक्ति क्षण भर में विदेश में बैठे व्यक्ति से भी बात कर लेता है. परन्तु मोबाइल के कारण ही लोगों को परिवार के सदस्यों से बात करने का समय नहीं मिल पाता. प्रत्येक स्थान पर लोग अपने मोबाइल के साथ व्यस्त दिखाई देते हैं. परिणामस्वरूप व्यक्ति का अकेलापन बढ़ता जा रहा है. व्यक्ति व्यक्ति से दूर होता चला जा रहा है. आवश्यकता है सामूहिक संवाद की प्रत्यक्ष संवाद मन से भाव से विचार से हमे जोड़ता है दुख :सुख में सहायक होकर साथ होने की अनुभूति प्रदान करता है। (लेखक-- डॉ. सौरभ मालवीय/ ईएमएस)

समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मानजनक कानून है

समान नागरिक संहिता को लेकर देशभर में एक बार फिर से बहस जारी है। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात बार-बार उठती रही है, परन्तु इस पर विवाद होने के पश्चात यह मामला दबकर रह जाता है। किन्तु जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई है, तब से यह मामला फिर से चर्चा में है। जहां भाजपा इसे देशभर में लागू करना चाहती है, वहीं मुस्लिम संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समाज में विवाह कानूनों को लेकर ब्रिटिश शासनकाल से ही विवाद होता रहा है, क्योंकि मुसलमानों में बहु पत्नी प्रथा का चलन है। शरीयत के अनुसार पुरुषों को चार विवाह करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय होगी, यह सर्वविदित है। पति जब चाहे पत्नी को तीन तलाक कहकर घर से निकाल देता है। ऐसी स्थिति में महिला का जीवन नारकीय बन जाता है। शाह बानो प्रकरण ने लोगों का ध्यान इस ओर खींचा था। वर्ष 1978 में शाह बानो नाम की वृद्धा को उसके पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया था। उसके पांच बच्चे थे। पीड़ित महिला के पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। उसके पति ने उसे गुजारा भत्ता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। इस पर महिला ने न्यायालय का द्वार खटखटाया। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में सात वर्ष लग गए। वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसके पति को निर्देश दिया कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को जीविकोपार्जन के लिए मासिक भत्ता दे। न्यायालय ने यह निर्णय अपराध दंड संहिता की धारा-125 के अंतर्गत लिया था। विदित रहे कि अपराध दंड संहिता की यह धारा सब लोगों पर लागू होती है चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंध रखते हों। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाती, परन्तु कट्टरपंथियों को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था का गठन किया तथा सरकार को देशभर में आन्दोलन करने की चेतावनी दे डाली। परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे झुक गए था तथा उनकी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। इससे शाह बानो के सामने जीविकोपार्जन का संकट खड़ा हो गया। मानवता के नाते जिस समाज को वृद्धा की सहायता करनी चाहिए थी, वही उसका शत्रु बन गया। आज भी यही स्थिति है। मुस्लिम समाज में शाह बानो जैसी महिलाओं की कमी नहीं है। मुस्लिम समाज में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि पति ने तीन तलाक कहकर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला का कोई साथ नहीं देता। मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पहले भाजपा सरकार ने तीन तलाक को रोकने का कानून बनाया और अब समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयासरत है। भाजपा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वर्ष 1998 में भी भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में सामान नागरिक संहिता कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले हमने समान नागरिक संहिता कानून लाने की घोषणा की थी। अब इसे विधानसभा से पारित करके कानून बना लिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इसे देश-प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। उनका यह भी कहना है कि प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए एक सम्मान का विषय है।

उल्लेखनीय है कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत देश में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके लागू होने की स्थिति में देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होगा, अर्थात कानून का किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में देश में कई निजी कानून लागू हैं, उदाहरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसाई पर्सनल लॉ एवं पारसी पर्सनल लॉ। इसी प्रकार हिंदू सिविल लॉ के अंतर्गत हिंदू, सिख एवं जैन समुदाय के लोग आते हैं।

समान नागरिक संहिता लागू होने से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा विवाह, तलाक एवं संपत्ति के मामले में सबके लिए एक ही कानून होगा।

इसके दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए सरकार से इसे लागू न करने की अपील है। बोर्ड का कहना कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी है। इसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है।

नि:संदेह देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से मुस्लिम समाज की महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। यह कानून मुस्लिम समाज से बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन करने में प्रभावी सिद्ध हो सकेगा, क्योंकि इस समाज के पुरुष अपनी पत्नी के जीवित रहते दूसरा, तीसरा एवं चौथा विवाह नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, संपत्ति में भी पुत्रियों को पुत्रों के समान ही भाग मिलेगा। इसमें दो मत नहीं है कि समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मानजनक कानून है, जो उन्हें सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देगा। (लेखक--डॉ. सौरभ मालवीय / ईएमएस)

आज का इतिहास 25 मई

1611 जहांगीर ने मेहरूनिसा से निकाह किया था.
1845 कैंटन चीन में सिनेमा गृह में अग्निकांड से 1,670 लोग मरे.
1877 स्ट्रीमर एस.एस.सर जान नारिस उड़ीसा के पास समुद्र में 732 व्यक्तियों सहित डूब गया.
1886 क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था.
1899 कवि नजरूल इस्लाम का जन्म हुआ.
1924 बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी का निधन हुआ.
1963 छह अफ्रीकी देशों ने अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की.
1969 सूडान में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया.
1979 अमरीकी विमान दुर्घटना में शिकागो के हवाई अड्डे पर 272 यात्री मारे गए.
1983 नील नदी में एक यात्री जहाज में आग लगने से 194 यात्री मारे गए और 68 अन्य लापता हो गए.
1998 प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का 61 वर्ष की आयु में निधन.
2002 उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले में बारात लेकर लौट रही एक बस पर बिजली का हाई टेंशन तार गिरने से लगी आग में 63 मरे.
2005 खेल मंत्री व अभिनेता सुनील दत्त का निधन.

शब्द पहेली - 7296

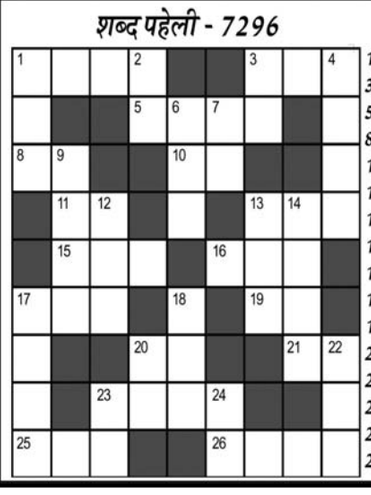

बाएँ से दाएँ

1.अँगरखा-4
3.मान-सम्मान,इज्जत-3
5.शुभाशीर्वाद,नियामत-4
8.केश-2
10.कसम,प्रतिज्ञा,वचन-2
11.बुरी आदत-2
13.मगरमच्छ-3
15.परिणाम-3
16.माँड़ी,स्टार्च-3
17.अक्षर (उर्दू-3)
19.रोम,केश-2
20.अधिकार,आरोप-2
21.सतह,स्तर,पटल-2
23.लूटपाट,डाका-4
25.सभ्यीकरण,विवेक-3
26.एक प्रसिद्ध कवि-4

ऊपर से नीचे

1.अनोखा,विचित्र,विलक्षण-3
2.नया,नवीन-2
3.इज्जत-2
4.कपोल-4
6.गमन,प्रेषित-3
7.पिता के पिता-2
9.चुनौती-4
13.गंदगी का ढ़ेर-3
14.असावधानी-4
17.जेल,कालकोठरी-4
18.शोर,ध्वनि,कंपन्न-3
20.ताप,शवदाह-2
22.यज्ञ,आहुति दान-3
23.रहस्य-2
24.जल, पानी-3

शब्द पहेली -7295 का हल

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

आईपीएल एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी और लखनऊ सुपर जाइंट्स में होगी कड़ी टक्कर

शाम 7.30 बजे से शुरु होगा मैच

कोलकाता (ईएमएस)। आईपीएल के 15वें सत्र में बुधवार को होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) और लखनऊ सुपर जाइंट्स आमने-सामने होंगे। आरसीबी इस सत्र में अपने खेल से ज्यादा किस्तम के भरोसे यहां तक पहुंची हैं और अब उसका लक्ष्य किसी भी प्रकार से यह मैच जीतना रहेगा। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली के फार्म में आने से भी टीम का हौंसला बढ़ा है। विराट ने इस सत्र में अब तक केवल दो अर्धशतक लगाये हैं पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम लीग मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाने के साथ ही अपने फार्म में आने का संकेत दिया है। विराट ने जिस प्रकार अंतिम लीग मुकाबले में 54 गेंद में 73 रन बनाए उससे उनके हौंसले बुलंद हैं अब उनका लक्ष्य अगले मैच में भी बड़ा स्कोर बनाना रहेगा।

आरसीबी को प्लेऑफ में जगह भी किस्मत के सहारे ही मिली है। अंतिम लीग मुकाबले में जीत के बाद भी उसकी राह कठिन थी पर दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस के हाथों हार से उसे अंतिम चार में प्रवेश मिल गया। आरसीबी को अगर लखनऊ पर जीत चाहिये तो विराट के अलावा कप्तान फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक को बड़ी पारियां खेलनी होंगी। कार्तिक ने जिस प्रकार इस सत्र में 'फिनिशर' की भूमिका निभाई है उन्हें उसे बरकरार रखना होगा। इसके अलावा गेंदबाजी में जोश हेजलवुड, वानिंदु हसरंगा और हर्षल पटेल को प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना होगा। टीम के पास तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी हैं हालांकि वह अब तक इस सत्र में असफल रहे हैं जिससे टीम को नुकसान हुआ है। आरसीबी ने अब तक एक बार भी खिताब नहीं जीता है और ऐसे में डु प्लेसी उसे जीत दिलाना चाहेंगे। तीन आईपीएल फाइनल खेल चुकी आरसीबी के पास कई स्टार खिलाड़ी हैं पर वह अंतिम चरण में बिखर जाती है। अब देखना है कि शांत तरीके से कप्तानी करने वाले डु प्लेसी उसे जीत दिला पाते हैं या नहीं।

नई पिच पर होने वाले नॉकआउट मैच में आरसीबी के गेंदबाजों का सामना करना नई टीम लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा। आरसीबी को इस मैच में कार्तिक से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कार्तिक को भी आईपीएल में ही अच्छे प्रदर्शन के कारण ही टीम इंडिया में फिर जगह मिली है ऐसे में वह अपने चयन को सही साबित करना चाहेंगे। इस बल्लेबाज ने अब तक 14 पारियों में 287 रन बनाये

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही आईटी कंपनियों के शेयरों में हुई बिकवाली से घरेलू बाजार नीचे आया है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 236 अंक तकरीबन 0.43 फीसदी गिरकर 54,052.61 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की शुरुआत बढ़त के साथ हुई पर वह उसके कायम नहीं रख पाया। यह एक समय 54,524.37 अंक के उच्च स्तर तक जाने के बाद 53,886.28 अंक के निचले स्तर तक भी पहुंचा। वहीं इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 89.55 अंक तकरीबन 0.55 फीसदी की गिरावट के साथ ही 16,125.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयरों को नुकसान हुआ जबकि दूसरी ओर डॉ रेड्डीज, एचडीएफसी, पावरग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और नेस्ले के शेयर लाभ में रहे। कारोबार के दौरान दवा, धातु, उपभोक्ता क्षेत्र के अलावा उर्जा और रीयल्टी इंडेक्स नीचे आये जबकि बीएसई मिडकैप इंडेक्स भी 0.8 फीसदी गिरे। स्माल कैप इंडेक्स भी 1 फीसदी फिसले। सुबह बाजार की शुरुआत तेजी से हुई पर कुछ देर बाद ही बिकवाली हावी होने से बाजार नीचे आने लगा और इसके बाद दिन भर यही हाल रहा। वहीं एशियाई बाजारों में भी गिरावट रही। चीन का शंघाई कंपोजिट, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की, हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा यूरोपीय बाजार भी नीचे आये हैं।

वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वें स्थान पर फिसला भारत

दावोस (ईएमएस)। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर 54वें स्थान पर आ गया है। हालांकि, दक्षिण एशियाई देशों में यह अब भी शीर्ष पर है। देश इस सूचकांक में 2019 में 46वें स्थान पर था। वैश्विक सूची में जापान शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का स्थान आता है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के दो साल पर जारी होने वाले यात्रा और पर्यटन क्षेत्र पर अध्ययन से यह भी पता चलता है कि यह क्षेत्र महामारी से उबर रहा है, लेकिन पुनरुद्धार अभी असंतुलित है और चुनौतियां कायम हैं।

यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 117 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया है। विश्व आर्थिक मंच में विमानन, यात्रा और पर्यटन मामलों के प्रमुख लॉरेन अपिंक ने कहा, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों ने अर्थव्यवस्थाओं में यात्रा और पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान को फिर से रेखांकित किया है। उन्होंने कहा दुनिया अब महामारी से उबर रही है, ऐसे में अर्थव्यवस्थाओं को यात्रा और पर्यटन अनुभवों को कई दशकों तक बेहतर बनाने को लेकर एक मजबूत परिवेश तैयार करने की जरूरत है।

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और कारोबारी यात्रा अब भी महामारी-पूर्व स्तर से नीचे है, लेकिन तेजी से टीकाकरण और घरेलू तथा प्रकृति से जुड़े पर्यटन की मांग से क्षेत्र में गतिविधियां मजबूत हो रही हैं।

उत्पाद शुल्क में कटौती व अन्य योजनाओं पर दी जा रही स्बिसिडी से तय सीमा को पार जा सकता है वित्तीय घाटा

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने जीडीपी का 6.4 फीसदी वित्तीय घाटे के रूप में लक्षित किया है, हालांकि, ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती व अन्य सरकारी योजनाओं के लिए दी जा रही सब्सिडी के कारण वित्तीय घाटा इस सीमा को पार कर सकता है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने इसके 6.7 से 6.9 फीसदी तक रहने का अनुमान लगाया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 6.7 फीसदी, कोटक इकोनॉमिक रिसर्च ने 6.8 फीसदी, बीओएफए सिक्योरिटीज ने 6.8-6.9 फीसदी और बार्कलेस, एमके ग्लोबल व मोतीलाल ओसवाल ने इसके 6.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

इसका सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा सब्सिडी और शुल्क में की गई कटौती है। दूसरी वजह सरकार की आय का घटना है। केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि उसे आरबीआई से 73,948 करोड़ रुपए का लाभांश मिलेगा, लेकिन केंद्रीय बैंक सरकार को केवल 30,307 करोड़ रुपए का लाभांश दे रहा है। यहां सरकार को 43,641 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों से सरकार को कोई लाभांश मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 83,000 करोड़ का घाटा दिख रहा है। साथ ही सरकार विनिवेश के लक्ष्य से भी 41,000 करोड़ रुपये पीछे चलती दिख रही है। बात करें सरकार के अतिरिक्त खर्च की तो केंद्र उर्वरक सब्सिडी पर 1,10,00 करोड़ रुपए, गरीब कल्याण अन्न योजना पर 80,000 करोड़ रुपए और गैस सिलिंडर सब्सिडी पर 6,100 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

वित्तीय घाटे की सीमा को लांघने को लेकर एक इंटरव्यू में आरबीई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये कैसे करेगी इसका जवाब उनके पास नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार के कदमों से भले मुद्रास्फीति कुछ हद तक काबू में आए लेकिन इससे एक समय के बाद इसका सीपीआई मुद्रास्फीति पर 50 बेसिस पॉइंट का डाउनग्रेड इंपेक्ट होगा। बार्कलेस के अनुसार, 8 जून को आरबीआई रेपो रेट में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करेगा और फिर अगस्त में भी 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखने को मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कोकाकोला बॉटलिंग इकाई पर 15 करोड़ जुर्माने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी कोका कोला की बॉटलिंग इकाई मून बेवरेजेज पर पर्यावरणीय उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए 15 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने मून बेवरेजेज की तरफ से दायर याचिका पर गाजियाबाद के निवासी को नोटिस भी जारी किया है, जिसकी शिकायत के आधार पर एनजीटी ने फैसला दिया था।

पीठ ने कहा एनजीटी की प्रधान पीठ के 25 फरवरी, 2022 को जारी आदेश को लागू करने पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने मून बेवरेजेज लिमिटेड की तरफ से एनजीटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है। एनजीटी ने कंपनी की ग्रेटर नोएडा इकाई पर 1.85 करोड़, साहिबाबाद इकाई पर 13.24 करोड़ और वरुण बेवरेजेज लिमिटेड की ग्रेटर नोएडा इकाई पर 9.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसके अलावा एनजीटी ने एक संयुक्त समिति भी गठित की थी जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सीजीडब्ल्यूए, यूपीजीडब्ल्यूडी और संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट शामिल थे। एनजीटी ने गाजियाबाद निवासी सुशील भट्ट की याचिका पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। भट्ट ने अपनी याचिका में मनमाने तरीके से भूजल को निकालने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि क्षेत्र में भूजल का वैसे ही संकट है, ऐसे में इन इकाइयों द्वारा अविवेकपूर्ण और मनमाने तरीके से जल निकाला जा रहा है।

केंद्र गेहूं के बाद अब चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र की भाजपानीत मोदी सरकार गेहूं की तरह चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार करीब छह साल में पहली बार चीनी निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। यह भी संभव है कि सरकार इस सीजन के निर्यात को 10 मिलियन टन पर सीमित कर दे।

आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। वहीं, ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने सितंबर को समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष में 18 मई तक 75 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। भारत से प्रमुख आयातक देश इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और अफ्रीकी देश हैं।

विपणन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में क्रमशः लगभग 6.2 लाख टन, 38 लाख टन और 59.60 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब शामिल हैं।

पेट्रोल और डीजल के बाद केंद्र सरकार कुछ और राहतें देने पर कर रही विचार

नई दिल्ली (ईएमएस)। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज डयूटी में बड़ी कटौती और रसोई गैस पर गरीबों को 200 रुपये की सब्सिडी देने के बाद कुछ और राहतों पर विचार कर रही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि एडिबल ऑइल जैसी चीजों पर कस्टम डयूटी घटाई जा सकती है। इसके अलावा आयात होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी राहत मिल सकती है। इससे कई उत्पादों के दामों में कमी आ सकती है। कई आयातों पर एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट सेस लगता है। उस पर भी कटौती किए जाने पर विचार चल रहा है। दरअसल सरकार महंगाई को थामने पर विचार कर रही है ताकि ब्याज दरों में इजाफा होने से अर्थव्यवस्था पटरी से न उतरने पाए।

वित्त मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह इस संबंध में मीटिंग की थी। शायद उसके बाद ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर राहत का फैसला लिया गया। अब अगले चरण में कुछ और चीजों में राहत दी जा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा टारगेट यह है कि महंगाई में 60 से 70 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी जाए। माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ही कमी करने से 40 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी आ सकती है। बता दें कि अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बेकाबू होकर 8 सालों के शीर्ष पर पहुंचते हुए 7.79 फीसदी हो गई थी। महंगाई दर के आंकड़ों में एक बेसिस पॉइंट का अर्थ 0.01 प्रतिशत होता है।

पाम ऑइल पर इंपोर्ट डयूटी को पहले ही सरकार कम कर चुकी है। कैनोला, राइस ब्रैन, ओलिव ऑइल आदि पर टैक्स कटौती किए जाने का विचार चल रहा है। इन सभी पर इंपोर्ट डयूटी में 35 फीसदी तक की कमी की जा सकती है। कुछ ऐसे रॉ मैटेरियल्स पर भी सरकार छूट देने का प्लान बना रही है, जिनके लिए भारत पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर रहता है। फिलहाल सरकार ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से उन उत्पादों की लिस्ट मंगाई है, जिन पर टैक्स में कटौती करके महंगाई में राहत दी जा सके। इसके अलावा सरकार की एक बड़ी कोशिश यह भी है कि पाम ऑइल पर निर्भरता कम की जा सके। पिछले दिनों इंडोनेशिया ने पाम ऑइल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अब भले ही इंडोनेशिया ने बैन हटा दिया है और कीमतों में कमी आ गई है, लेकिन अब सरकार इसके विकल्प के ही तलाश की कोशिश में जुटी है। भारत को हर साल 9 मिलियन टन पाम ऑइल का आयात करना पड़ता है। यह भारत की कुल एडिबल ऑइल की खपत का 40 फीसदी हिस्सा है। इसके अलावा यूक्रेन से सूरजमूखी के तेल का आयात भी 90 फीसदी तक प्रभावित हुआ है।

पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र भारत के जामनगर में स्थापित : डब्ल्यूएचओ

जिनेवा (ईएमएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारत सरकार ने मिलकर गुजरात के जामनगर में पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया है, ताकि प्रैक्टिस और उत्पादों के प्रभाव के संबंध में भरोसेमंद साक्ष्य और आंकड़े जुटाए जा सकें। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने कहा, ''लगभग 90 प्रतिशत सदस्य देशों के पारंपरिक औषधि के इस्तेमाल को मान्यता देकर पिछले महीने ही हमने पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र भारत में स्थापित किया है, ताकि प्रैक्टिस और उन उत्पादों के प्रभाव के संबंध में भरोसेमंद साक्ष्य और आंकड़े जुटाए जा सकें, जिनका इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं।

उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार ने पारंपरिक औषधि के लिए डब्ल्यूएचओ का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। पारंपरिक औषधि के लिए वैश्विक ज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 25 करोड़ डॉलर के निवेश के जरिये सहायता की है। इसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिये दुनिया भर से पारंपरिक औषधि की क्षमता का दोहन करना है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करती है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि उसे 194 सदस्य देशों में से 170 ने बताया कि वे पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं। विश्व निकाय ने बताया कि इन देशों की सरकारों ने प्रैक्टिस और उत्पादों के प्रभाव के संबंध में भरोसेमंद साक्ष्य और आंकड़े जुटाने के लिये डब्ल्यूएचओ से सहायता मांगी थी। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डब्ल्यूएचओ प्रमुख और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ जामनगर में वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी थी।

टाइम पत्रिका ने 100 रसूख वाली हस्तियों की सूची में गौतम अदाणी और एडवोकेट करुणा नंदी को दिया स्थान

न्यूयार्क (ईएमएस)। अंतरराष्ट्रीय टाइम पत्रिका ने रसूखदार हस्तियों की सूची में भारतीय दिग्गज बिजनेसमेन गौतम अदाणी और एडवोकेट करुणा नंदी स्थान दिया है। पत्रिका ने 2022 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है। टाइम ने गौतम अदाणी के बारे में लिखा है कि कभी क्षेत्रीय स्तर से शुरुआत करने वाले अदाणी आज एयरपोर्ट, निजी बंदरगाहों, सौर और तापीय ऊर्जा और उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार से जुड़े हैं। साथ ही टाइम मैग्जीन ने कहा कि अदाणी दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के दिग्गज कारोबारी हैं, लेकिन वे लोगों की नजरों से दूर रहते हैं और चुपचाप अपना कारोबारी साम्राज्य बढ़ाने में लगे हैं।

पत्रिका ने करुणा नंदी को महिला अधिकारों की चैंपियन बताया है, जो कोर्ट के अंदर और बाहर अपनी आवाज को सशक्त तरीके से पेश करती हैं। साथ ही नंदी के बारे में कहा गया कि वे महिला अधिकारों की पैरोकार हैं। जिन्होंने दुष्कर्म विरोधी कानूनों में सुधार की हिमायत की और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मुकदमे लड़े हैं। इस सूची में जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सला वोन डेर लेयन, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, एपल के सीईओ टिम कुक और मीडिया दिग्गज ओप्रा विन्फ्रे शामिल हैं।

इसके साथ ही टाइम पत्रिका ने अपने 100 प्रतिभाशाली लोगों में मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े चैनिंग टैटम, पीट डेविडसन, अमांडा सेफ्राइड, जेंडाया, एडेल, सिमू लियू, मिला कुनिस, ओपरा विनफ्रे, अहमिर क्वेस्टलोव थाम्पसन, मैरी जे ब्लिज, मिरांडा लैम्बर्ट, जान बैटिस्ट और कीनू रीव्स को अपनी लिस्ट में जगह दी है। इसके अलावा एथलीट्स में नाथन चेन, एलेक्स मार्गन, एलीन गु, कैंडेस पार्कर, एलेक्स मार्गन, मेगन रैपिनो और बेकी सारब्रुन और राफेल नडाल का नाम है।

बढ़ती महंगाई से दुनियाभर के देशों के प्रमुख दिख रहे चिंतित

लंदन (ईएमएस)। बढ़ती महंगाई दुनियाभर के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर रही है। यह न सिर्फ अविकासशील और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल हो रहे दुनियाभर के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने इस पर चिंता जाहिर की है। कीमतों में उछाल की वजह से न सिर्फ उपभोक्ताओं का सेंटीमेंट बिगड़ा है, बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों को भी इसका झटका लग रहा है। इस काबू में करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व सहित दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंकों को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। इसकारण डॉलर में मजबूती आ रही है।

रूस-यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 के कारण चीन में लगे लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल और खाद्य बाजार में कीमतों में आई उछाल पर विराम लगता फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसकारण और निराशा हो रही है। जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक ने कहा कि हमारे सामने कम से कम चार ऐसी समस्याएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। बढ़ती महंगाई, ऊर्जा का संकट, खाद्य संकट (फूड पॉवर्टी) और पर्यावरण संकट हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ एक संकट पर ध्यान केंद्रित करते रहे, तब दूसरी अन्य समस्याओं को नहीं सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी समस्या हल नहीं होती है, तब मुझे वास्तव में डर है कि हम वैश्विक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। इसका वैश्विक स्थिरता पर जबरदस्त प्रभाव है।

आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि युद्ध, सख्त वित्तीय स्थिति और कीमतों में उछाल, खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी ने स्पष्ट रूप से ग्लोबल आउटलुक को अंधेरे में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी की अभी संभावना नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से परिदृश्य से बाहर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्किल साल होने वाला है। रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतों का बढ़ना बड़ी समस्या बनी हुई है।

यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड ने चेतावनी दी कि महंगाई और विकास विपरीत रास्ते पर है। कीमतों में उछाल का असर आर्थिक गतिविधियों और घरेलू खरीद क्षमता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध अति-वैश्वीकरण के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित हो सकता है। इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा है और लागत में बढ़ोतरी हो हुई है।

शेयर बाजार में उथल-पुथल- शीर्ष निवेशक मार्क मोबियस बोले- जितना टूट चुका, उतना ही और गिर...

नई दिल्ली (ईएमएस)। अनिश्चितता के बीच झूल रहे भारतीय शेयर बाजार में लंबे अंतराल से उथल-पुथल का क्रम चल रहा है। मंगलवार को भी निफ्टी हरे निशान में खुला, लेकिन कुछ समय बाद ही इसमें गिरावट आ गई। आज यह सूचकांक 89.55 अंकों की गिरावट के साथ 16,125.15 पर बंद हुआ है। यह अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 13 फीसदी नीचे आ चुका है। दुनिया के दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस का कहना है कि दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट जारी है। इस मंदी से भारतीय बाजार भी अछूते नहीं है। उनका कहना है कि भले ही भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आए, परंतु अन्य शेयर बाजारों की तुलना में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसलिए इसमें निवेशकों को निवेश करते रहना चाहिए।

मनीकंट्रोल डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय शेयर बाजार में अभी और गिरावट आएगी। भारतीय बाजार अपने ऑल टाइम हाई से 30 फीसदी तक फिसल सकते हैं। केवल भारतीय बाजार ही नहीं गिर रहे हैं बल्कि अन्य शेयर बाजार भी अब मंदी की चपेट में हैं। मोबियस कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी के फाउंडर और दुनिया के दिग्गज निवेशक का कहना है कि दूसरे बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मोबियस ने निवेशकों को सलाह दी है कि ऐसी भारतीय कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन पर कम कर्ज है और जिनकी प्राइसिंग पावर मजबूत है।

भारतीय शेयर बाजार में पिछले काफी दिनों से गिरावट जारी है। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई 18,604 से अब तक 13 फीसदी टूट चुका है। निफ्टी में साल 2022 में अब तक 8.49 फीसदी लुढ़क चुका है। पिछले छह महीनों में इसमें 7.38 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले महीने में ही इसने 4.86 फीसदी का गोता लगाया है। इसी तरह बीएसई सेंसेक्स भी वर्ष 2022 में अब तक 8।74 फीसदी टूट चुका है। पिछले एक महीने में इसमें 4.54 फीसदी की गिरावट आई है तो पिछले छह महीने में यह 7.42 फीसदी टूट चुका है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले 8 महीनों के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है।

मनी लॉर्डिंग मामले में ईडी ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण का बयान दर्ज किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। मनी लॉर्डिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण का बयान दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उसके और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत रामकृष्ण का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने की कार्यवाही जेल के अंदर दो बार में की गई। उन्होंने कहा कि बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने छह मार्च को रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में हैं। उनके ऊपर एनएसई के कामकाज में अनियमितताओं के आरोप हैं।

संघीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रही है। आयकर विभाग एनएसई में अनियमितताओं के इन आरोपों की जांच करने वाली तीसरी एजेंसी है। ईडी की धनशोधन जांच एनएसई को-लोकेशन मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इसके अलावा आनंद सुब्रमण्यम को मुख्य रणनीतिक सलाहकार बनाए जाने और बाद में उन्हें समूह परिचालन अधिकारी तथा तत्कालीन एमडी (रामकृष्ण) का सलाहकार बनाए जाने में कथित रूप से प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच भी की जा रही है। ईडी ने पिछले महीने को-लोकेशन मामले में शामिल दलालों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी।

पीएम मोदी ने लॉन्च की क्वॉड फेलोशिप, 100 बेस्ट छात्रों को मिलेगा लाभ

टोक्यो (ईएमएस)। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की अगुआई में मंगलवार को टोक्यो में क्वॉड समिट 2022 का आयोजन किया गया। इस समिट में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने शिरकत की। क्वॉड समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 'क्वॉड फेलोशिप' कार्यक्रम लॉन्च किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय छात्रों से क्वॉड फेलोशिप के लिए आवेदन करने की अपील की।

उन्होंने कहा मैं अपने छात्रों को 'क्वाड' फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने और मानवता के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले नवप्रवर्तकों की अगली पीढ़ी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। समिट में कहा गया कि हर क्वॉड देश से 25 छात्रों यह लाभ दिया जाएगा, कुल 100 छात्रों को ये फेलोशिप दी जाएगी।

इसके तहत अमेरिका में प्रमुख विश्वविद्यालयों में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए हर साल 100 छात्रों को स्पॉन्सर किया जाएगा। क्वाड में पहली बार शिक्षा का विषय सामने आया है। क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम के तहत गरीब देशों के 100 छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से एक दूसरे के देशों में अध्ययन करने में सक्षम करेगा। क्वॉड फेलोशिप प्रोग्राम अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में 100 असाधारण अमेरिकी, जापानी, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय मास्टर और डॉक्टरेट छात्रों को प्रायोजित करेगा। फेलोशिप विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का एक नेटवर्क विकसित करेगी जो निजी, सार्वजनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में, अपने स्वयं के देशों में और क्वाड देशों के बीच नवाचार और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रत्येक क्वाड फेलो को 50,000 का एकमुश्त पुरस्कार मिलेगा। जिसका उपयोग टयूशन, शोध, फीस, किताबें, कमरे और संबंधित शैक्षणिक खर्चों (जैसे, पंजीकरण शुल्क, शोध-संबंधित यात्रा) के लिए किया जा सकता है। सभी क्वाड फेलो स्नातक स्तर के अध्ययन को पूरा करने से संबंधित लागतों को कवर करने के लिए 25,000 तक की अलग-अलग प्रदर्शित जरूरतों पर आधारित वित्तपोषण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

फेलोशिप के आवेदन के लिए आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। अगस्त 2023 तक एसटीईएम क्षेत्र में बैचलर डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। स्नातक स्तर पर बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आवेदक वर्तमान में किसी मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम में नामांकित है, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं।

क्वाड फेलोशिप के लिए चयन होने पर, फेलो इलेक्ट के पास विभिन्न प्रकार के वर्चुअल संसाधनों और प्रोग्रामिंग तक पहुंच होगी, जो कोहॉर्ट के भीतर कनेक्शन बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं क्योंकि वे स्नातक प्रवेश प्रक्रिया को नेवीगेट करते हैं। अगस्त से शुरू होकर शैक्षणिक वर्ष के अंत तक फेलो, एसटीईएम और समाज के इंटरसेक्शन पर विषयों की अपनी समझ को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल प्रोग्रामिंग अवसरों के बाद एक आवासीय अनुभव में भाग लेंगे। क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम से स्नातक होने पर, सीनियर फेलो के पास उन संसाधनों तक पहुंच होगी जो कॉहोर्ट्स और क्वाड देशों में आजीवन नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं।

सोशल मीडिया की लत के लिए कंपनियों को दोषी ठहरा सकेंगे माता-पिता, किया जा सकेगा मुकदमा

सैक्रामेंटो (ईएमएस)। कैलिफोर्निया के निवासी सोशल मीडिया कंपनियों को उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए जल्द ही जिम्मेदार ठहरा सकेंगे, जो उनके उत्पादों के आदी हो गए हैं। राज्य की असेम्बली में एक विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत सोशल मीडिया लत के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों पर मुकदमा करने का प्रावधान है।

यह विधेयक अब राज्य की सीनेट में भेजा जाएगा। व्यावसायिक समूहों ने चेतावनी दी है कि यदि यह प्रस्ताव कानून बन जाता है, तो सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी जोखिम का सामना करने के बजाय कैलिफोर्निया में बच्चों के लिए संचालन बंद कर देंगी।

यह विधेयक केवल उन सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होगा, जिनका सकल राजस्व पिछले साल कम से कम 10 करोड़ डॉलर था। यह विधेयक फेसबुक जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों को लक्षित करने वाला प्रतीत होता है। यह नेटफ्लिक्स और हुलु जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं या केवल ईमेल और संदेश भेजने वाली सेवाओं की पेशकश करने वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा। विधेयक पेश करने वाले रिपब्लिकन नेता जॉर्डन कनिंघम ने कहा बच्चों पर निरंकुश सामाजिक प्रयोग करने का युग अब खत्म हो गया है और हम बच्चों की रक्षा करेंगे।

ऐसा महंगा छाता किस काम का, जो बारिश से नहीं बचाता

-छाते की कीमत है सवा लाख रुपये, चीन में मचा है बवाल

बीजिंग (ईएमएस)। दुनिया की लग्जरी ब्रांड गुच्ची और स्पोर्ट्सवियर फर्म एडिडास चीन में एक ऐसा छाता बेचने की तैयारी में हैं, जिसकी कीमत एक लाख 27 हजार रुपये है। इस छाते को लेकर चीन में बवाल मच गया है कि इतना महंगा छाता आखिर किस काम का है जो बारिश नहीं रोक पाता है। इस बारे में कंपनी गुच्ची का कहना है कि यह छाता वाटरप्रूफ नहीं है और यह धूप से बचाने या डेकोरेटिव यूज के लिए है। चीन के सोशल मीडिया में इस छाते को लेकर हंगामा मचा हुआ है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैबो में इस छाते से जुड़ी पोस्ट वायरल हो गई है। लोग जमकर इसे ट्रोल कर रहे हैं। इस छाते को अगले महीने चीन के बाजार में उतारने की तैयारी चल रही है। यह गुच्ची और एडिडास

छोटे और सीमांत आदिवासी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है 'कृषि विविधीकरण योजना' : मुख्यमंत्री

- राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 1.23 लाख आदिवासी किसानों के लिए प्रारंभ की कृषि विविधीकरण योजना 2022-23

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के अंबाजी से उमरगाम तक के आदिवासी बेल्ट में रहने वाले आदिवासी किसानों की कृषि आय में वृद्धि कर खेती को विविधतापूर्ण और टिकाऊ बनाने की मंशा जताई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गांधीनगर से राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 1 लाख 23 हजार आदिवासी किसानों को कृषि विविधीकरण योजना 2022-23 के अंतर्गत खाद एवं बीज किट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि विविधीकरण की इस योजना के तहत इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए उत्तर और मध्य गुजरात के 7 जिलों के लगभग 75,000 आदिवासी किसानों को मक्के के बीज और खाद किट का वितरण किया जाएगा। दक्षिण गुजरात के 7 जिलों के लगभग 48,000 लाभार्थियों को सब्जियों के संशोधित बीज व खाद की किट वितरित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2012 से लागू की गई राज्य सरकार की कृषि विविधीकरण की इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 30 से 35 करोड़ रुपए के खर्च से लगभग 1 लाख से अधिक आदिवासी किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। तदअनुसार, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवल्ली, महीसागर, दाहोद, पंचमहाल, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरुच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड़ और डांग समेत 14 आदिवासी बहुल जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। अब तक ऐसे 11.69 लाख किसानों को योजना का लाभ दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि बरसों से परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे आदिवासी बंधुओं की खेती से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, तब कृषि विविधीकरण सहायता ऐसे छोटे और सीमांत आदिवासी किसानों को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में इस वर्ष से ऑनलाइन पोर्टल पर आदिवासी लाभार्थी किसानों का पंजीकरण शुरू किया गया है। इस पारदर्शी पद्धति में पंजीकरण से लेकर लाभ की मंजूरी तक के सारे विषयों को ऑनलाइन किया गया है। इससे आदिवासी किसानों को अब आवेदन के लिए कार्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा तथा उन्हें घर बैठे ही अपनी अर्जी के विवरणों का पता चल सकेगा। पटेल ने यह भी कहा कि यह ऑनलाइन पद्धति प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभ को सीधे लाभार्थी के हाथों में पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रणाली के अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल डांग जिला संपूर्ण प्राकृतिक खेती वाला जिला बना है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विविधीकरण के साथ-साथ गाय आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाएं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में 143 आश्रम शालाओं को भवन निर्माण के लिए एक क्लिक के जरिए 83.96 करोड़ रुपए का प्रोत्साहक अनुदान भी भेंट किया। उल्लेखनीय है कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बच्चों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने आश्रम शालाएं शुरू की हैं। आदिजाति विभाग के अंतर्गत राज्यभर की 661 आश्रम शालाओं में लगभग 91 हजार से अधिक जनजातीय बच्चों को आवास, भोजन के साथ कक्षा 1ली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर जनजातीय क्षेत्र में कृषि का दायरा बढ़ाने के साथ ही आदिवासी बच्चों को शिक्षा की भी सुविधा मुहैया कराकर विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आदिवासी बहुल जिले साबरकांठा के लाभार्थी आदिवासी किसानों के साथ संवाद भी किया। लाभार्थी किसानों ने इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता के जरिए अनाज उत्पादन और बिक्री से बड़ा आर्थिक सहारा मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया तथा योजना से हुए लाभ की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और आदिवासी लाभार्थी किसान 14 जिलों के विभिन्न स्थलों से जुड़े थे।

मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम 26 मई गुरुवार को आयोजित होगा

- भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में नवनिर्मित 'राज्य स्वागत' कक्ष में आवेदकों को प्रत्यक्ष सुनेंगे

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आगामी 26 मई, 2022 गुरुवार को राज्य स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में उपस्थित रह कर गांधीनगर में आवेदकों के पक्ष को प्रत्यक्ष सुनेंगे तथा उनकी समस्या के उचित निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। राज्य के नागरिकों-जनता-जनार्दन की शिकायतों-प्रस्तुतियों का टेक्नोलॉजी तथा संवाद-मार्गदर्शन के माध्यम से निवारण करने वाला इस 'स्टेट वाइड अटेंशन ऑन पब्लिक ग्रिवेंसेस बाय एप्लिकेशन ऑफ़ टेक्नोलॉजी' (ऐंउ– स्वागत) कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान वर्ष 2003 से कराया था। इतना ही नहीं, इस 'स्वागत' ऑनलाइन कार्यक्रम को गुड गवर्नेंस तथा जनसमस्याओं के सुचारु निवारण की श्रेष्ठता से जुड़े संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अवॉर्ड सहित कई अवॉर्ड भी मिले हैं। यह राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होता है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं नागरिकों की शिकायतें प्रत्यक्ष सुनते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 26 मई, 2022 गुरुवार को अपराह्न 3 बजे गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल 2 के तलघर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सुविधा से लैस विशाल बैठक क्षमता वाले नवनिर्मित स्वागत कक्ष में राज्य स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तहसील स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम हर महीने के चौथे बुधवार को और ज़िला स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम हर महीने के चौथे गुरुवार को सुबह आयोजित होता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम के बाद ज़िला स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सहभागी हुए ज़िला अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने चार साल से गायब महिला को ढूंढ निकाला

ंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में 18 साल की लड़की ने चार साल से गुमशुदा माँ के साथ रहने की बात कही, महिला ने अपनी बेटी के साथ रहने के बजाय, परिवार से अलग रहकर अपने पति के साथ रहने का फैसला किया

अहमदाबाद : अहमदाबाद की एक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक 18 वर्षीय लड़की की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को ध्यान में रखते हुए चार साल से लापता एक महिला को खोज निकालने का आदेश दिया जिसे पुलिस ने पूरा करते हुए महिला को ढूंढ निकाला। मामले की सुनवाई के दौरान लड़की ने चार साल से लापता अपनी मां के साथ रहने की मांग की है। जिसमें हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अहमदाबाद की असलाली पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और हाई कोर्ट के सामने पेश किया। हालांकि, इसके बाद महिला ने अपनी बेटी के साथ रहने के बजाय, परिवार से अलग रहकर अपने पति के साथ रहने का फैसला किया।

बता दें कि महिला की 2018 में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। हालांकि असलली पुलिस महिला का पता लगाने में नाकाम रही। इसलिए, महिला की बेटी ने उसे खोजने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया। ऐसे में हाईकोर्ट ने पुलिस से पूरे मामले की क्रोनोलॉजी पूछी। इसके बाद पुलिस ने महिला को खोज निकाला।

महिला 2018 से लापता थी और असलाली पुलिस उसका पता लगाने में नाकाम रही थी। उच्च न्यायालय द्वारा उसे खोजने के लिए किए गए प्रयासों का कालक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। इस महिला के खिलाफ संपत्ति विवाद में कई मामले लंबित हैं।

हार्दिक पटेल के अगले सप्ताह भाजपा में शामिल होने की संभावना

अहमदाबाद (ईएमएस) कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हार्दिक पटेल अगले सप्ताह भाजपा का भगवा धारण कर सकते हैं जानकारी के मुताबिक भाजपा हाईकमांड ने हार्दिक पटेल के पार्टी में शामिल करने की हरी झंडी दे दी हैं बता दें कि गत 18 मई को हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी प्रमुख समेत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे दे दिया थ जिसके बाद से वह किस पार्टी में शामिल होंगे इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे राममंदिर और धारा 370 समेत कई मुद्दों को लेकर हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी समेत भाजपा सरकार की तारीफ की थी जिससे लगता था कि हार्दिक पटेल भाजपा जॉइन कर सकते हैं, लेकिन कब यह तय न थ अब जानकारी है कि हार्दिक पटेल आगामी 30 मई को भाजपा में विधिवत शामिल हो जाएंगे बताया जाता है कि हार्दिक पटेल की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी गुजरात दौरे के वक्त या फिर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गांधीनगर में होनेवाले सहकार सम्मेलन के दौरान भाजपा जॉइन करें लेकिन भाजपा हाईकमांड ने हार्दिक पटेल की इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया हैं इसलिए अब हार्दिक पटेल आगामी 30 मई को गुजरात प्रदेश भाजपा मुख्यालय कमलम में भगवा धारण कर सकते हैं हार्दिक पटेल के साथ उनके करीबी भी भाजपा जॉइन कर सकते हैं संभावना है कि केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस मौके पर गुजरात प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे

कांग्रेस विधायक स्व. अनिल जोशियारा के पुत्र हजारों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल

अरवल्ली (ईएमएस) गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं एक ओर कांग्रेस प्रदेश संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं दूसरी ओर एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी के साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं आज भिलोडा से कांग्रेस विधायक स्व. डॉ. अनिल जोशियारा के बेटे केवल जोशियारा ने अपने हजारों को समर्थकों के साथ भाजपा का भगवा धारण कर लिया अरवल्ली जिले के भिलोडा में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात भाजपा प्रमुख सीआर पाटील ने केवल जोशियारा समेत उनके हजारों समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया केवल जोशियारा ने कहा कि भाजपा में शामिल होने का उनका निजी फैसला हैं मैं काफी समय से भाजपा शासन में विकास देख रहा हूं, वह फिर भिलोडा का हो, गुजरात का या फिर देश का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों को देख मैंने भाजपा जॉइन करने का फैसला किया हैं केवल जोशियारा ने कहा कि जब तक मेरे पिता जीवित थे, तब उनके साथ सेवा कार्य करता था और अब भाजपा में शामिल कर उन्हीं कामों को आगे बढ़ाऊंगा कांग्रेस के गढ़ में जीत के सवाल पर केवल जोशियारा ने कहा कि हार-जीत तो आनेवाला वक्त ही बताएगा भाजपा भिलोडा से मुझे उम्मीदवार बनाएगी या नहीं यह भी तय नहीं हैं चुनाव के एक महीने पहले इसका पता चलेगा केवल ने कहा कि वह भाजपा में बगैर किसी शर्त के शामिल हुए हैं भाजपा जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगा उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर गुजरात के लोग भाजपा का काम देख अबकी बार उसे जिताएंगे केवल जोशियारा ने यह भी बताया कि सोमवार को गुजरात कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकोर ने उनसे संपर्क कर भाजपा में शामिल नहीं होने की नसीहत दी थी साथ ही कांग्रेस पूरा सम्मान देने का आश्वासन भी दिया थ लेकिन मुझे कांग्रेस से ज्यादा भाजपा पर भरोसा था, इसलिए मैंने आज भाजपा जॉइन की हैं गौरतलब है कि भाजपा आगामी चुनाव में आदिवासी सीटें जीतने के लिए एडीचोटी का जोर लगा रही हैं कुछ समय पहले कांग्रेस के खेडब्रह्मा से विधायक अश्विन कोटवाल भाजपा में शामिल हुए थे उस वक्त ही केवल जोशियारा ने भाजपा जॉइन करने की मंशा जाहिर कर दी थी, जिसे आज उन्होंने पूरी कर दी

मीशो प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या 6 लाख के पार पहुँची, लगभग आधे विक्रेता विशिष्ट

राष्ट्रीय, 16 मई, 2022: भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट कॉमर्स कंपनी, मीशो ने घोषणा की कि उनके प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या 6 लाख के पार पहुँच चुकी है और अप्रैल 2021 के बाद से इस संख्या में 7 गुनी वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में कंपनी द्वारा शुरू की गई इंडस्ट्री की कुछ प्रथम पहलों जैसे शून्य कमीशन और शून्य जुर्माना के परिणामस्वरूप मीशो से जुड़ने वाले छोटे व्यवसायों की संख्या बढ़ी है।

इनमें से आधे से अधिक विक्रेता केवल मीशो से परिचालन करते हैं, जिससे यह देश भर के छोटे और मध्यम व्यवसायों का पसंदीदा ई - कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है।

मीशो के कुल विक्रेताओं में 70ज्ञ सेअधिकविक्रेताअमृतसर, राजकोट और सूरत जैसे टियर 2+ शहरों से हैं। कंपनी जनवरी 2021 से 11 लाख छोटे व्यवसाय के मालिकों को लखपति और 5,000 से अधिक को करोड़पति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विक्रेताओं को विशाल और विविधीकृत ग्राहक आधार की आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम बनाए जाने से उनकी कमाई क्षमता बढ़ गई है।

कांग्रेस हमेशा से राम विरोधी रही है, यही उसकी असलियत है : हार्दिक पटेल

अहमदाबाद (ईएमएस) कांग्रेस नेता भरतसिंह सोलंकी के बयान को लेकर बवाल मच गया हैं कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की यही असलियत है वह पहले से ही राम विरोधी रहे हैं और आज फिर वह बात सामने आ गई। हार्दिक ने अपने ट्वीट में लिखा ''मैंने पहले भी कहा था की कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करती है, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने बयान दिया की राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते ह्रह्ष्ठ!'' मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूँ की आपको भगवान राम से क्या दुश्मनी है? अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान राम के खिलाफ अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं। बता दें कि वटामण में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया थ भरतसिंह सोलंकी ने कहा कि भाजपा ने राम नाम पर लोगों को ठगा और करोड़ों रुपयों की उगाही की इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में रखी ईंटों पर कूत्ते पेशाब करते थे भरतसिंह के इस विवादित बयान को लेकर बवाल मच गया हैं

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122, 9327086467 R.N.I. 63177/95